

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2606

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।
20 अग्रहायण, 1946 (शक)

डिजिटल हब की स्थापना

2606. श्री यदुवीर वाडियार:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मैसूर के उभरते सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी क्षेत्र की सहायता करने के लिए डिजिटल इंडिया योजना का लाभ किस प्रकार उठाया जा रहा है; और
- (ख) क्या सरकार का इस योजना के अंतर्गत मैसूर में डिजिटल हब स्थापित करने अथवा स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): भारत सरकार छोटे शहरों और कस्बों में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं।

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) इस प्रयास में सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत, मैसूर जैसे टियर -2 और टियर -3 शहरों में 57 केंद्रों के साथ पूरे भारत में 65 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए गए हैं। एसटीपी केंद्र इनक्यूबेटर सुविधा प्रदान करते हैं जो उद्यमियों को अपने अभिनव विचारों को स्टार्टअप में बदलने में मदद करते हैं। इनक्यूबेटर सुविधा विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और उत्कृष्टता केंद्रों के कार्यान्वयन के माध्यम से उद्यम पूंजीपतियों (वीसी) जैसे निवेशकों, आईआईटी/एनआईटी/उद्योग के सलाहकारों के साथ बैठक करने और आईटी पेशेवरों के साथ नेटवर्किंग का अवसर प्रदान करती है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई), मैसूर केंद्र के साथ 32 आईटी/आईटीईएसइकाइयों को पंजीकृत किया गया है, जिससे वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1,726.84 करोड़ रुपये का निर्यात हो पाया है।
